Daily Current Affairs in Hindi 6 November 2018

वित्त और बैंकिंग से संबंधित वर्तमान मामले

आरबीआई ने बाहरी वाणिज्यिक उधार मानदंडों को आराम दिया, होल्डिंग अवधि को कम किया

- भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने मंगलवार को बुनियादी ढांचे कंपनियों के लिए बाहरी वाणिज्यिक उधार (ईसीबी) मानदंडों को आराम दिया और कुछ हेजिंग प्रावधानों को बदल दिया।
- केंद्रीय बैंक ने बुनियादी ढांचे में ईसीबी के लिए न्यूनतम 5 वर्ष से 3 साल तक न्यूनतम औसत परिपक्वता आवश्यकता को कम कर दिया है, जबकि पात्र उधारकर्ताओं के लिए औसत परिपक्वता अवधि की आवश्यकता को कम करने के लिए वर्तमान में 10 वर्षों से पूरी तरह से 5 साल तक अपने जोखिम को हेजिंग करने से छूट दी गई है। ।
- इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेस में 3 से 5 साल की न्यूनतम औसत परिपक्वता अवधि वाले ईसीबी को भी 100 प्रतिशत अनिवार्य हेजिंग आवश्यकता को पूरा करना होगा।
- इस कदम से उन फर्मों को मदद मिलेगी जो घरेलू बाजारों में तंग तरलता की स्थिति और ब्याज दरों में तेजी लाने के कारण विदेशी मुद्रा जुटाने की तलाश में हैं। ईसीबी के प्रवाह में कोई भी वृद्धि रुपये-डॉलर विनिमय दर पर दबाव कम करेगी।

अगले 5 महीनों में पीएसबी को 1.2 लाख करोड़ रुपये की पूंजीगत पूंजी की जरूरत है: क्रिसिल

- सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक के बीच मतभेद हैं और विवादित मुद्दों में से एक प्रॉम्प्ट सुधारक कार्रवाई (पीसीए) है, जो कमजोर और बुरे ऋण से भरे बैंकों को प्रतिबंधित करता है।
- यह सरकार के लिए एक तंग रस्सी चलना है - अपने राजकोषीय घाटे को नियंत्रण में रखते हुए और बैंकों को पर्याप्त रूप से पूंजीकरण करने के लिए, ताकि वे स्वतंत्र रूप से उधार दे सकें।
- यह मुश्किल हो जाएगा क्योंकि क्रिसिल अनुमान से पता चलता है कि बेसल III मानदंडों को पूरा करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को पांच महीने में 1.2 लाख करोड़ रुपये के निवेश की ताजा स्तरीय पूंजी की जरूरत है।
- यह अनुमान लगाया गया था कि इससे पहले 21,000 करोड़ रुपये अधिक थे, जब सरकार ने बेसल III मानदंडों को पूरा करने के लिए अक्टूबर 2017 में 2.11 लाख करोड़ रुपये की पुनर्पूंजीकरण की घोषणा की थी।
- भारतीय स्टेट बैंक जैसे बड़े बैंक स्तरीय-द्वितीय बॉन्ड के माध्यम से पुनर्पूंजीकरण के लिए अपनी योजनाओं को सूचीबद्ध कर रहे हैं और उचित समय पर इक्विटी मुद्दे की प्रतीक्षा कर रहे हैं, पीसीए के तहत कमजोर बैंकों को सरकार को उन्हें आवश्यक पूंजी प्रदान करने की आवश्यकता है।

प्रतिबंध के बावजूद खाता खोलने के के लिए आरबीआई ने फिनो पेमेंट्स बैंक लिमिटेड पर $ 136.9K (INR 1 करोड़) जुर्माना लगाया

- सोमवार (5 नवंबर) को एक नई अधिसूचना में, भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा कि उसने फिनो पेमेंट्स बैंक लिमिटेड पर $ 136.9K (INR 1 करोड़) जुर्माना लगाया है।

- प्रतिबंध के बावजूद नए खाते खोलने के लिए केंद्रीय बैंक ने 31 अक्टूबर, 2018 को जुर्माना लगाया ।
- केंद्रीय बैंक ने नोट किया कि मुंबई स्थित फिनो पेमेंट्स बैंक पर "कुछ लाइसेंस शर्तों के उल्लंघन और भुगतान बैंक के लिए संचालन दिशानिर्देशों के उल्लंघन के कारण आगे के निर्देशों तक नए खातों को खोलने के लिए दिशा का उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया है।"
- फिनो पेमेंट्स बैंक के पास 1 एमएन का ग्राहक आधार था और अगले साल मार्च तक इस आंकड़े को 3 एमएन तक बढ़ाने की योजना बना रहा है।
- फर्म अगस्त में आरबीआई के साथ परेशानी में उतरा, जब शीर्ष बैंक ने ग्राहक खातों में जमा सीमाओं पर परिचालन दिशानिर्देशों का पालन करने के लिए उचित प्रक्रियाओं को स्थापित करने का निर्देश दिया।

5000 एकड़ से अधिक परियोजना के दूसरे चरण के लिए पंजाब ने क्वार्कसिटी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए

- पंजाब सरकार ने मंगलवार को क्वार्कसिटी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए, जिसमें परियोजना के दूसरे चरण में अत्याधुनिक औद्योगिक पार्क, औद्योगिक मॉडल कस्बों और एकीकृत टाउनशिप बनाने के लिए 5000 एकड़ में फैलाया गया। पूरे राज्य में।
- मुख्यमंत्री कप्तान अमरिंदर सिंह और कई कैबिनेट मंत्रियों की उपस्थिति में एमओयू पर सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे।
- कप्तान अमरिंदर सिंह ने क्वार्कसिटी मोहाली के चेयरमैन फ्रेड इब्राहिमी को बधाई दी कि युवाओं के लिए भारी नौकरी क्षमता पैदा करने के अलावा राज्य भर में औद्योगिक और आर्थिक गतिविधियों को उत्प्रेरित करने के लिए अपनी क्वार्कसिटी परियोजना का विस्तार के लिए।
- एक सुझाव के जवाब में, मुख्यमंत्री ने पंजाब ब्यूरो ऑफ इनवेस्टमेंट प्रमोशन को नियमित रूप से उन उद्योगपतियों के लंबित अनुप्रयोगों की प्रगति की निगरानी करने का निर्देश दिया जो राज्य में अपने उद्यम स्थापित करने के इच्छुक थे, ताकि उनके प्रारंभिक कार्यान्वयन को सुविधा मिल सके।

अमेरिका ने भारत, चीन को ईरानी तेल खरीदने के लिए अपनी मंजूरी से छूट दी

- 5 नवंबर, 2018 को संयुक्त राज्य अमेरिका ने ईरानी तेल खरीदने के लिए अमेरिकी प्रतिबंधों से भारत सहित आठ देशों को अस्थायी रूप से छूट दी।
- वाशिंगटन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए, अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पिओ ने अस्थायी रूप से प्रतिबंधों से मुक्त देशों की सूची की घोषणा की। देशों में भारत, चीन, जापान, इटली, ग्रीस, दक्षिण कोरिया, ताइवान और तुर्की शामिल हैं। पोम्पेओ ने कहा कि ट्रम्प प्रशासन ने तेहरान पर प्रतिबंधों को दोबारा शुरू करने के बाद इन देशों ने फारस की खाड़ी देश से तेल खरीद में उल्लेखनीय कमी देखी है।
- साथ ही, पोम्पिओ ने विश्व स्तर पर कंपनियों को चेतावनी दी कि यदि वे ईरान के साथ वाणिज्यिक लेनदेन जारी रखते हैं तो वे संभावित प्रतिबंधों सहित गंभीर जुर्माना के अधीन होंगे। यह कहते हुए कि अमेरिका ईरान के लिए अपना व्यवहार बदलना चाहता है, पोम्पो ने कहा कि इसके केंद्र में आर्थिक दबाव का अभूतपूर्व अभियान है।
- संयुक्त राज्य अमेरिका का मुख्य उद्देश्य पूरे मध्य पूर्व और दुनिया भर में हिंसक और अस्थिर गतिविधियों को वित्त पोषित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले राजस्व के ईरानी शासन को भूखा करना है।

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने विकास उद्देश्यों के लिए 6 सीमावर्ती राज्यों को 113 करोड़ रुपये जारी किया

- 5 नवंबर, 2018 को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इन अलग-अलग स्थानों में रहने वाले लोगों की स्थिति में सुधार के लिए सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम (बीएडीपी) के तहत 6 सीमावर्ती राज्यों को 113.36 करोड़ रुपये जारी किए।
- ये 6 सीमावर्ती राज्य असम, नागालैंड, सिक्किम, गुजरात, राजस्थान और उत्तराखंड हैं।
- इसके साथ ही, गृह मंत्रालय ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाले राज्यों के लिए 2018-19 के दौरान कुल 637.98 करोड़ रुपये जारी किए हैं। ये फंड 177 राज्यों में अंतरराष्ट्रीय सीमा के साथ स्थित गांवों के सर्वांगीण विकास के लिए 2017-18 में जारी 1100 करोड़ रुपये के अतिरिक्त थे।
- सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम 1 986-87 में पाकिस्तान के सीमावर्ती राज्यों, जम्मू-कश्मीर, पंजाब, गुजरात और राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों के संतुलित विकास के लिए शुरू किया गया था और बाद में यह सभी भूमि सीमाओं तक बढ़ा दिया गया था।
- अब, अंतर्राष्ट्रीय सीमा के 50 किलोमीटर के भीतर रहने वाले लोगों पर ध्यान केंद्रित करने के साथ सीमावर्ती आबादी की विशेष विकास आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बीएडीपी में 17 राज्यों में 111 सीमावर्ती जिलों को शामिल किया गया है।
- 17 राज्य अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल हैं।

भारत और राज्यों से संबंधित वर्तमान मामले

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फैजाबाद को अयोध्या के रूप में नामित किया

- इलाहाबाद को प्रयाग राज के रूप में नामित करने के बाद, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को फैजाबाद को अयोध्या के रूप में दोबारा नामित किया, इस कदम में विशेषज्ञों ने कहा कि संभावित रूप से सत्तारूढ़ बीजेपी को हिंदुत्व एजेंडा को अगले साल लोकसभा चुनावों से आगे बढ़ने के लिए आगे बढ़ाना होगा। उन्होंने यह भी घोषणा की कि अयोध्या में हवाई अड्डे का नाम भगवान राम के नाम पर रखा जाएगा।
- विश्व हिंदू परिषद (वीएचपी) ने मांग की कि फैजाबाद को श्री अयोध्या नाम दिया जाए। दीवाली की पूर्व संध्या पर बोलते हुए, 'योगी जी मंदिर के निर्मन कारो' मंत्र के बीच योगी ने कहा कि अयोध्या के साथ कोई अन्याय नहीं किया जा सकता है।
- योगी ने कहा कि उनकी सरकार विभिन्न विकास परियोजनाओं की शुरूआत के माध्यम से अयोध्या के विकास के लिए प्रतिबद्ध थी। वीएचपी के प्रवक्ता शरद शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार को उन शहरों का नाम बदलना चाहिए जो गुलामी की मांग करते हैं।
- अयोध्या के रूप में फैजाबाद का नाम बदलने के लिए सीएम की घोषणा अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के आसपास लगातार बढ़ते झगड़े के बीच आता है।

मणिपुर सरकार ने स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया

- मणिपुर सरकार ने मंगलवार को आईएल एंड एफएस टाउनशिप और शहरी संपत्ति लिमिटेड और प्राइसवाटरहाउस कूपर्स प्राइवेट लिमिटेड (परियोजना प्रबंधन सलाहकार के रूप में) के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए। मुख्यमंत्री के सचिवालय में इम्फाल में स्मार्ट सिटी परियोजना के कार्यान्वयन के लिए यह किया गया ।
- कंपनी इम्फाल में स्मार्ट सिटी मिशन के तहत स्मार्ट सिटी परियोजनाओं को डिजाइन, विकसित, प्रबंधित और कार्यान्वित करेगी, जो कि तीन वर्षों के भीतर पूरा होने की उम्मीद है।
- मुख्यमंत्री एन बिरेन सिंह, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री एल जयंतकुमार, मुख्य सचिव डॉ जे सुरेश बाबू और सचिव (राजस्व) टी रणजीत की उपस्थिति में समझौता ज्ञापन हुआ था।
- राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व नगरपालिका प्रशासन, आवास और शहरी विकास (एमएएचयूडी) विभाग के निदेशक टी एच हरिकुमार ने किया और निजी कंपनी को उसकी हेड-शहरी परियोजना (पूर्व और उत्तर-पूर्व) चंदन रॉय चौधरी द्वारा प्रतिनिधित्व किया गया ।

भारत की परमाणु पनडुब्बी आईएनएस अरिहंत ने पहला 'निवारण गश्त' पूरा किया

- 5 नवंबर, 2018 को प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की कि भारत की पहली स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी आईएनएस अरिहंत ने सफलतापूर्वक अपना पहला प्रतिबंध गश्त पूरा कर लिया है।
- विकास दर्शाता है कि पानी के नीचे की युद्धपोत ने अपना पहला दीर्घकालिक मिशन "लाइव" परमाणु-टिपित मिसाइलों के साथ पूरा कर लिया है। इस अवसर पर, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रक्रिया में शामिल सभी लोगों को बधाई दी, विशेष रूप से महान उपलब्धि के लिए आईएनएस अरिहंत के दल।
- 6,000 टन आईएनएस अरिहंत, जो एक उच्च वर्गीकृत कार्यक्रम के तहत तीन दशकों तक विकास में था, प्रधान मंत्री मोदी की अध्यक्षता में परमाणु कमांड अथॉरिटी के प्रत्यक्ष नियंत्रण में आता है।
- अपने "निवारण गश्ती" के सफल समापन के बाद, आईएनएस अरिहंत को अब पूरी तरह कार्यात्मक पानी के नीचे बैलिस्टिक मिसाइल वितरण मंच माना जा सकता है।

पर्यटन मंत्री ने आईजीआई हवाई अड्डे पर पर्यटक सुविधा काउंटर का उद्घाटन किया

- 5 नवंबर, 2018 को पर्यटन मंत्री के जे अल्फोन्स ने नई दिल्ली में इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पर्यटक सुविधा और सूचना काउंटर का उद्घाटन किया।
- सुविधा काउंटर आईजीआई हवाई अड्डे के टर्मिनल -3 आगमन द्वार पर स्थित है।
- केंद्र का उद्देश्य उन पर्यटकों की मदद करना है जो देश की यात्रा करेंगे। काउंटर पर्यटन मंत्रालय के 24x7 हेल्पलाइन - 1363 से जुड़ा होगा।
- पर्यटन मंत्रालय मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, गया और वाराणसी में सुविधा काउंटर भी शुरू कर रहा है।

एचएएल नई सुविधा से अधिक तेजस सेनानियों बनाएगा

- राज्य संचालित एयरोस्पेस प्रमुख हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल) महाराष्ट्र में नासिक में अपनी नई उत्पादन सुविधा से अधिक लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट (एलसीए) तेजस पेश करेगा।
- कंपनी तेजस लड़ाकू उत्पादन संवर्द्धन के लिए 1,300 करोड़ रुपये का निवेश कर रही है।
- रक्षा कंपनी के पास बेंगलुरु में दो उत्पादन इकाइयां हैं जहां उन्नत चौथी पीढ़ी के बहु-भूमिका प्रकाश सेनानियों को भारतीय वायुसेना (आईएएफ) युद्ध के बेड़े के लिए बनाया गया है।
- नई सुविधा 2020 तक परिचालित होने की उम्मीद है।

भुवनेश्वर मेरा वाई-फाई' लॉन्च हुआ

- 5 नवंबर, 2018 को ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने भुवनेश्वर स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा 'भुवनेश्वरमे वाई वाई-फाई' लॉन्च किया ताकि शहर अपने प्रमुख स्थानों पर पहुंच सके।
- पहले दिन 275 एक्सेस पॉइंट्स (एपी) के साथ प्रमुख स्थानों में स्थित 100 हॉटस्पॉट लाइव हो गए।
- एक वाई-फाई हॉटस्पॉट किसी भी समय 150 उपयोगकर्ताओं को संभालने में सक्षम होगा और इंटरनेट की गति 2 मेगा बाइट प्रति सेकेंड (एमबीपीएस) पर उपलब्ध होगी।
- नागरिकों के लिए डेटा उपयोग पर कोई शुल्क नहीं होगा, जब वे इस नेटवर्क के माध्यम से सरकारी सेवाओं तक पहुंचेंगे। इसके अलावा, दिए गए दिन किसी भी उपयोगकर्ता के लिए 250 एमबी डेटा तक पहुंच मुक्त होगी।
- मुफ्त 250 एमबी दैनिक डेटा की खपत के बाद, एक व्यक्ति को लॉग इन करने और बाद के उपयोग के लिए भुगतान योजना चुननी होगी। 'भुवनेश्वर मेरा वाई-फाई' उपयोगकर्ताओं के लिए बहुत कम लागत वाली शीर्ष योजना प्रदान करेगा।

खेल से संबंधित वर्तमान मामले

लखनऊ स्टेडियम का नाम बदलकर अटल बिहारी वाजपेयी रखा गया

- 5 नवंबर, 2018 को लखनऊ के नव निर्मित एकाना इंटरनेशनल स्टेडियम का नाम बदलकर पूर्व प्रधान मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखा गया था। स्टेडियम अब 'भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम' के रूप में जाना जाएगा।
- स्टेडियम का नाम बदलकर पहले अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच - भारत और वेस्टइंडीज के बीच टी -20 इंटरनेशनल के ठीक पहले रखा गया था। शहर ने 6 नवंबर, 2018 को स्टेडियम में अपना पहला अंतरराष्ट्रीय मैच आयोजित किया जब भारत ने दूसरे टी -20 अंतरराष्ट्रीय मैच में वेस्टइंडीज के खिलाफ खेला।
- छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह ने आगामी राजधानी नई रायपुर को अटल नगर के रूप में नाम बदलने की घोषणा की।
- योगी आदित्यनाथ की अगुआई वाली उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रस्तावित बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को 'अटल पथ' के रूप में नामित करने का भी फैसला किया।
- एम्स ऋषिकेश ऑडिटोरियम, गुजरात में साबरमती नदी पर एक घाट और मॉरीशस में साइबर टावर का नाम भी उनके नाम पर रखा जाएगा।

नियुक्तियों से संबंधित वर्तमान मामले

सुप्रीम कोर्ट के महासचिव उत्तराखंड के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होंगे

- सीजेआई रंजन गोगोई की अध्यक्षता में कॉलेजिअम ने सुप्रीम कोर्ट के महासचिव रविंद्र मैथानी के नाम उत्तराखंड उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में उन्नयन के लिए सिफारिश की है।
- मैथानी का नाम दो अन्य न्यायिक अधिकारियों नारायण सिंह धनिक और रमेश चंद्र खुलेबे के साथ मंजूरी दे दी गई थी।
- 29 मई, 2018 को मौजूद तीन रिक्तियों को भरने के लिए उत्तराखंड उच्च न्यायालय के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश की सिफारिश पर निर्णय लिया गया।

विश्व से संबंधित वर्तमान मामले

तुर्की ने इस्तांबुल में दुनिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा खोल दिया

- इस्तांबुल के बाहर तुर्की के राष्ट्रपति तैयिप एर्डोगान द्वारा दुनिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा अनावरण किया गया था।
- नया $ 11.7 बिलियन दुनिया का सबसे व्यस्ततम होगा, हालांकि यह जनवरी तक पूरी तरह से परिचालित नहीं होगा। नए हवाई अड्डे का नाम इस्तांबुल हवाई अड्डा होगा।
- हवाई अड्डे के लिए मोबाइल एप्लिकेशन और कृत्रिम बुद्धि का उपयोग करता है, ऊर्जा कुशल है और एक उच्च तकनीक सुरक्षा प्रणाली का दावा करता है।
- हवाई अड्डे के अंदरूनी तुर्की और इस्लामी डिजाइनों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और इसके ट्यूलिप के आकार वाले वायु यातायात नियंत्रण टावर ने 2016 अंतर्राष्ट्रीय वास्तुकला पुरस्कार जीता था ।